

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 30 जून, 2004/9 आषाढ़, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 30 जून, 2004

संख्या वि० स०-लैज-बजट/1-27/2004.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2004

(2004 का विधेयक संख्यांक 5) जो आज दिनांक 30 जून, 2004 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाजटा, ^१/_२
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2004

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अधिक धनराशियों जिनका योग 70,96,55,53,000 रुपये (सत्तर अरब, छियानव करोड़, पचपन लाख, तिरपन हजार रुपये) है, संदत और उपयोजित की जाएं, जिनका वित्तीय वर्ष 2004-2005 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों के संदाय को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए 70,96,55,53,000 रुपये की राशि जारी करना।

3. इन अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत और उपयोजित करने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जाएगा। विनियोग।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3		
		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	कुल
		रुपए	रुपए	रुपए
1	विधान सभा (राजस्व)	6,57,48,000	17,51,000	6,74,99,000
	(पूँजी)	1,00,00,000	—	1,00,00,000
2	राज्यपाल और मंत्रि-परिषद् (राजस्व)	4,34,44,000	1,57,77,000	5,92,21,000
	(पूँजी)	—	—	—
3	न्याय प्रशासन (राजस्व)	32,21,51,000	6,54,11,000	38,75,62,000
	और निर्वाचन (पूँजी)	70,01,000	—	70,01,000
4	सामान्य प्रशासन (राजस्व)	45,39,24,000	2,11,47,000	47,50,71,000
	(पूँजी)	5,00,000	—	5,00,000
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन (राजस्व)	1,43,14,58,000	—	1,43,14,58,000
	(पूँजी)	—	—	—
6	आवकारी और कराधान (राजस्व)	15,83,62,000	—	15,83,62,000
	(पूँजी)	—	—	—
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व)	1,87,98,90,000	—	1,87,98,90,000
	(पूँजी)	10,45,43,000	—	10,45,43,000
8	शिक्षा (राजस्व)	9,55,16,99,000	—	9,55,16,99,000
	(पूँजी)	27,66,90,000	—	27,66,90,000
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राजस्व)	2,65,65,28,000	—	2,65,65,28,000
	(पूँजी)	53,97,81,000	—	53,97,81,000
10	लोक निर्माण— (राजस्व)	1,28,47,58,000	—	1,28,47,58,000
	भवन (पूँजी)	8,09,26,000	—	8,09,26,000
11	कृषि (राजस्व)	71,26,25,000	—	71,26,25,000
	(पूँजी)	33,20,00,000	—	33,20,00,000
12	उद्यान (राजस्व)	46,49,27,000	—	46,49,27,000
	(पूँजी)	7,95,00,000	—	7,95,00,000
13	मिचवाई और बाढ़ नियन्त्रण (राजस्व)	65,46,71,000	—	65,46,71,000
	(पूँजी)	1,18,11,74,000	—	1,18,11,74,000
14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य (राजस्व)	64,30,88,000	—	64,30,88,000
	(पूँजी)	2,49,90,000	—	2,49,90,000
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (राजस्व)	1,07,74,13,000	—	1,07,74,13,000
	(पूँजी)	19,08,01,000	—	19,08,01,000
16	वन और वन्य जीवन (राजस्व)	1,43,82,69,000	—	1,43,82,69,000
	(पूँजी)	1,37,51,000	—	1,37,51,000

1	2	3	4	5
		रुपये	रुपये	रुपये
17	सड़कें और पुल (राजस्व)	3,08,54,14,000	—	3,08,54,14,000
	(पूँजी)	1,37,85,02,000	1,40,00,000	1,39,25,02,000
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज (राजस्व)	51,63,22,000	—	51,63,22,000
	(पूँजी)	5,18,00,000	—	5,18,00,000
19	सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता (राजस्व)	1,29,54,92,000	—	1,29,54,92,000
	(पूँजी)	4,47,01,000	—	4,47,01,000
20	ग्रामीण विकास (राजस्व)	96,93,78,000	—	96,93,78,000
	(पूँजी)	20,00,000	—	20,00,000
21	सहकारिता (राजस्व)	10,84,99,000	—	10,84,99,000
	(पूँजी)	1,15,53,000	—	1,15,53,000
22	खाद्य और भाण्डागारण (राजस्व)	9,87,49,000	—	9,87,49,000
	(पूँजी)	53,11,000	—	53,11,000
23	जल और विद्युत विकास (राजस्व)	57,03,51,000	—	57,03,51,000
	(पूँजी)	27,00,01,000	—	27,00,01,000
24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राजस्व)	10,67,49,000	—	10,67,49,000
	(पूँजी)	56,00,000	—	56,00,000
25	सड़क और जल परिवहन (राजस्व)	31,55,93,000	—	31,55,93,000
	(पूँजी)	10,30,00,000	—	10,30,00,000
26	पर्यटन और नागर विमानन (राजस्व)	3,25,90,000	—	3,25,90,000
	(पूँजी)	1,27,00,000	—	1,27,00,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (राजस्व)	21,09,97,000	—	21,09,97,000
	(पूँजी)	4,04,50,000	—	4,04,50,000
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास (राजस्व)	2,32,05,94,000	—	2,32,05,94,000
	(पूँजी)	1,34,99,07,000	89,17,000	1,35,88,24,000
29	वित्त (राजस्व)	6,77,02,18,000	17,58,30,69,000	24,35,32,87,000
	(पूँजी)	6,40,01,000	5,01,00,15,000	5,07,40,16,000
30	विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व)	16,77,15,000	—	16,77,15,000
	(पूँजी)	1,81,55,000	—	1,81,55,000
31	जनजातीय विकास (राजस्व)	2,02,31,70,000	50,000	2,02,32,20,000
	(पूँजी)	61,52,92,000	—	61,52,92,000
	(राजस्व)	41,43,07,86,000	17,68,72,05,000	59,11,79,91,000
	(पूँजी)	6,81,46,30,000	5,03,29,32,000	11,84,75,62,000
	जोड़	48,24,54,16,000	22,72,01,37,000	70,96,55,53,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में ले वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख : 30 जून, 2004.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग फाईल संख्या फिन0-ए0-सी0(1)-5/2004]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की विषय-वस्तु के बारे में सचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करत हैं।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2004

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि)।

शिमला :

30 जून, 2004.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 5 of 2004

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 2004

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year 2004-2005.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2004.

Issue of a sum of Rs. 70,96,55,53,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2004-2005.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to a sum of Rs. 70,96,55,53,000 (Seventy hundred ninety six crores, fifty five lakhs, fifty three thousand rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2004-2005 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

+1 Demand No.	2 Services and purposes	3 Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha (Revenue)	6,57,48,000	17,51,000	6,74,99,000
	(Capital)	1,00,00,000	—	1,00,00,000
2	Governor and (Revenue)	4,34,44,000	1,57,77,000	5,92,21,000
	Council of Ministers (Capital)	—	—	—
3	Administration of (Revenue)	32,21,51,000	6,54,11,000	38,75,62,000
	Justice and Election (Capital)	70,01,000	—	70,01,000
4	General Adminis- (Revenue)	45,39,24,000	2,11,47,000	47,50,71,000
	tration (Capital)	5,00,000	—	5,00,000
5	Land Revenue (Revenue)	1,43,14,58,000	—	1,43,14,58,000
	and District Adminis- (Capital)	—	—	—
6	Excise and Taxation (Revenue)	15,83,62,000	—	15,83,62,000
	(Capital)	—	—	—
7	Police and Allied (Revenue)	1,87,98,90,000	—	1,87,98,90,000
	Organisations (Capital)	10,45,43,000	—	10,45,43,000
8	Education (Revenue)	9,55,16,99,000	—	9,55,16,99,000
	(Capital)	27,66,90,000	—	27,66,90,000
9	Health and Family (Revenue)	2,65,65,28,000	—	2,65,65,28,000
	Welfare (Capital)	53,97,81,000	—	53,97,81,000
10	Public Works— (Revenue)	1,28,47,58,000	—	1,28,47,58,000
	Buildings (Capital)	8,09,26,000	—	8,09,26,000
11	Agriculture (Revenue)	71,26,25,000	—	71,26,25,000
	(Capital)	33,20,00,000	—	33,20,00,000
12	Horticulture (Revenue)	46,49,27,000	—	46,49,27,000
	(Capital)	7,95,00,000	—	7,95,00,000
13	Irrigation and Flood (Revenue)	65,46,71,000	—	65,46,71,000
	Control (Capital)	1,18,11,74,000	—	1,18,11,74,000
14	Animal Husbandry, (Revenue)	64,30,88,000	—	64,30,88,000
	Dairy Development (Capital)	2,49,90,000	—	2,49,90,000
	and Fisheries			
15	Planning and Back- (Revenue)	1,07,74,13,000	—	1,07,74,13,000
	ward Area Sub-Plan (Capital)	19,08,01,000	—	19,08,01,000
16	Forest and Wild Life (Revenue)	1,43,82,69,000	—	1,43,82,69,000
	(Capital)	1,37,51,000	—	1,37,51,000
17	Roads and Bridges (Revenue)	3,08,54,14,000	—	3,08,54,14,000
	(Capital)	1,37,85,02,000	1,40,00,000	1,39,25,02,000
18	Supplies, Industries (Revenue)	51,63,22,000	—	51,63,22,000
	and Minerals (Capital)	5,18,00,000	—	5,18,00,000
19	Social Justice and (Revenue)	1,29,54,92,000	—	1,29,54,92,000
	Empowerment (Capital)	4,47,01,000	—	4,47,01,000

1	2		3		
			Rs.	Rs.	Rs.
20	Rural Development	(Revenue)	96,93,78,000	—	96,93,78,000
		(Capital)	20,00,000	—	20,00,000
21	Co-operation	(Revenue)	10,84,99,000	—	10,84,99,000
		(Capital)	1,15,53,000	—	1,15,53,000
22	Food and Warehousing	(Revenue)	9,87,49,000	—	9,87,49,000
		(Capital)	53,11,000	—	53,11,000
23	Water and Power	(Revenue)	57,03,51,000	—	57,03,51,000
	Development	(Capital)	27,00,01,000	—	27,00,01,000
24	Printing and	(Revenue)	10,67,49,000	—	10,67,49,000
	Stationery	(Capital)	56,00,000	—	56,00,000
25	Road and Water	(Revenue)	31,55,93,000	—	31,55,93,000
	Transport	(Capital)	10,30,00,000	—	10,30,00,000
26	Tourism and Civil	(Revenue)	3,25,90,000	—	3,25,90,000
	Aviation	(Capital)	1,27,00,000	—	1,27,00,000
27	Labour, Employment	(Revenue)	21,09,97,000	—	21,09,97,000
	And Training	(Capital)	4,04,50,000	—	4,04,50,000
28	Water Supply,	(Revenue)	2,32,05,94,000	—	2,32,05,94,000
	Sanitation, Housing	(Capital)	1,34,99,07,000	89,17,000	1,35,88,24,000
	and Urban Development				
29	Finance	(Revenue)	6,77,02,18,000	17,58,30,69,000	24,35,32,87,000
		(Capital)	6,40,01,000	5,01,00,15,000	5,07,40,16,000
30	Miscellaneous	(Revenue)	16,77,15,000	—	16,77,15,000
	General Services	(Capital)	1,81,55,000	—	1,81,55,000
31	Tribal Development	(Revenue)	2,02,31,70,000	50,000	2,02,32,20,000
		(Capital)	61,52,92,000	—	61,52,92,000
		(Revenue)	41,43,07,86,000	17,68,72,05,000	59,11,79,91,000
		(Capital)	6,81,46,30,000	5,03,29,32,000	11,84,75,62,000
	Grand Total		48,24,54,16,000	22,72,01,37,000	70,96,55,53,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the year, 2004-2005.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
the 30th June, 2004.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A- C (1)-5/2004]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 2004, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 2004

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year, 2004-2005.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

Surinder Singh Thakur,
Secretary (Law).

SHIMLA ;
the 30th June, 2004.